for 1991-92 under the Centrally Sponsored Accelerated Rural Water Supply Programme was Rs. 47.24 crores and under the State Sector Minimum Needs Programme Rs. 79.00 crores for Uttar Pradesh. This amount was used for provision of drinking water through handpumps, tube-wells, gravity feed schemes in rural areas. No allocation is made separately for provision of handpumps alone.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य

845. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या थे और अभी तक कितने लक्ष्य प्राप्त किए हैं ;

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को ठीक प्रकार से कार्यान्वित न किए जाने के संबंध में अभी तक कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जिसे उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा था, का 1989-90 से जवाहर रोजगार योजना नामक एक नए कार्यक्रम में विलय कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत प्रगति की निगरानी श्रम दिनों में सृजित रोजगार के रूप में की जाती है । जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1991-92 के लिए उत्तर प्रदेश हेतु निर्धारित 1472.69 लाख श्रमदिनों के रोजगार सृजन के लक्ष्य के मुकाबले 1592.14 लाख श्रमदिनों का रोजगार सृजित किया है । चूंकि निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है , अतः उपचारात्मक कदम उठाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1991-92 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में जवाहर रोजगार योजना की निधियों का दुरूपयोग करने और योजना को ठीक प्रकार से कार्यान्वित न किए जाने के संबंध में इस मंत्रालय में 12 शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इन शिकायतों की जांच तथा उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकार को भेज दिया गया था ।

Special Investigations Divisions to Identify problem villages

846. DR. ABRAR AHMED: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government of India provide Central assistance to the State to establish special investigation divisions to carry out identification of problem villages where there is no water source;

(b) the number of village identified so far in this regard; and

(c) the relief provided by Government in such villages so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Special Investigation Divisions were established in the Fourth Five Year Plan to carry out identification of problem villages. Central assistance is now given for monitoring and investigation units working in the States/Union Territories for monitoring of physical and financial progress of rural water supply and for survey and investigation carried out for schemes under ARWSP. The Central assistance is now limited to Rs. 10 lakh per annum for each State and Rs. 4 lakhs per annum for each Union Territory.

(b) and (c) In the 1980 survey, 2.31 lakh problem villages were